SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I have mentioned it right at the start.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK): He has given this assurance.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Sir, I am on a point of order. My point of order is this. The Finance Minister has very kindly indicated what the paper contains. We are not having a debate on that right now. But the issues which we have raised are of a nature which will require additional papers on the connected issues, so that the debate really takes place in its full richness. We have raised such issues which are not covered by the paper but which should be integrated in this discussion. I would like to know whether, before we discuss it in the House, he will circulate such papers also.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Sir, I may tell the hon. Member. Mr. Nirmal Chatterjee that if he can formulate and give some suggestions. I can give thought to it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK): Now we take up Calling Attention. Shri Chaturanan Mishra to continue.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Need to ensure remunerative prices for agricultural produce particularly for Paddy, Wheat and Sugarcane in view of the unprecedented hike in the prices of agricultural inputs

श्री चतुरानन मिश्र : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि कृषि पदार्थों के मूल्यों को डिप्रेस करने के लिए हम आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं तो इस संबंध में जो सावधानी बरतनी चाहिए, वह सावधानी सरकार नहीं बरत रही है । मैंने अभी पिटीशन कमेटी की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई कि कैसे उस आयात के चलते, इम्पोर्ट के चलते नारियल के दामों में कमी हो गई । इसको हमने देखा । इस तरह से आर्टिफिशियल फायबर, एच.इ.डी.पी. मैन्यूल उसका भी जो आयात होता है, इम्पोर्ट होता है, उसके चलते रुई पर, कॉटन के दाम पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है । रबर के संबंध में भी यही बात है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी विदेश में, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जो एक मन्दी के काल से गुजर रहा है और उस हालत में जो विकसित देशों की सरकारें हैं, सबसिडाइज करके चीजें विदेशों में भेजती हैं । तो हमारे देश में अगर उसका डम्प कर दिया जाता है तो हमारी इकोनोमी बर्बाद होती है, इसके संबंध में मंत्री महोदय के बयान में कुछ भी नहीं है । इसलिए मैं चाहूंगा इस प्रश्न की ओर भी सरकार स्पष्टीकरण करें ।

मैं एक और सवाल उठाना चाहूंगा कि कोई सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए किसानों के जो सामान हैं उनके मूल्य में और होलसेल प्राइस जो हैं, उसके मूल्य में । पिछले पांच वर्ष के अगर हम होलसेल प्राइस इण्डेक्स को देखें तो उसमें कर ब 65 परसेंट राइज हुआ है, लेकिन अगर हम धान की कीमत को देखें तो 50 परसेंट भी उसमें राइज नहीं हुआ है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो होलसेल प्राइज राइज होती है तो उससे कृषि पदार्थों में जो निर्धारित मूल्य होता है, उसका क्या रिलेशनशिप रहेगा, उसके संबंध में जरा स्पष्टीकरण दें । ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, वह बताएं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक और प्रश्न उठाऊंगा कि जो किसानों का सामान, कच्चा माल है और उसको लेकर जब माल तैयार हो जाता है तो तैयार माल का जो दाम बढ़ता है; उसका सबंध किसानों के कच्चे माल से कहां तक रहता है ? मैं आप के सामने कुछ आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं रा-कॉटन के संबंध में । रा-कॉटन का दाम जनवरी, 1985 में 236.8 पर था और वह घट कर 86 के मार्च में 183.3 हो गया । यह इतनी रा-कॉटन की प्राइस घट गई, लेकिन उससे जो कपड़ा

बनता है, उसका दाम जनवरी, 1985 में 261.13 था और वह लगातार बढ़ता रहा और मार्च, 1986 में 268.8 पर पहुंच गया। मैं यह चाहता हूं कि जब रूई का दाम घट गया तो फिर इसका रिफ्लेक्शन अगर कपड़े के मूल्य में भी घटती में हो, तो जन-साधारण को उसका फायदा मिल सकता है। अब यहां किसान दोहरी मार खाता है, एक तो रूई सस्ता बेचे और कपड़ा महंगा खरीदे। यह दोहरी लूट जो है, इसको रोकने के लिये कोई भी आप का प्रबंध नहीं है, आपके बयान में नहीं है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में वे अपना स्पष्टीकरण करें कि कैसे यह हुआ।

एक और प्रश्न उठता है कि किसान लगातार कोशिश करते हैं जूट के मामले में, रूई के मामले में और चीनी के मामले में कि इतना उत्पादन बढ़ाते जिससे देश सेल्फ-सफिसिएंट की ओर जाता है। मैं इसकी चर्चा इसलिये भी कर रहा हूं, जब हमारा विदेश व्यापार का सालाना घाटा 8000 करोड़ को भी क्रास करने वाला है, आगे जा रहा है, तब अगर किसानों का यह एफर्ट होता है कि हम देश को आत्म-निर्भर बनाएं तो आप अपनी मूल्य नीति के चलते उनका सारा हौसला तोड़ देते हैं और फिर निर्यात करने की दिशा में चले जाते हैं। तिलहन के बारे में यही हुआ, चीनी के बारे में यही हुआ और लगातार ऐसी बातें हो रही हैं, रबर के बारे में भी यही हुआ। इसलिये हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में भी सरकार स्पष्टीकरण करे।

मैं एक और प्रश्न करना चाहता हूं। यह सही बात है कि कुछ सिंथेटिक सामान बन रहे हैं, आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जा रहे हैं, जो हमारे जूट के उत्पादन को एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। इसी तरह से आर्टिफिशियल सिंथेटिक सामान हमारे काटन पर भी इफेक्ट करने जा रहा है, एडवर्सली इफेक्ट करने के लिये जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि न सिर्फ अपने विभागीय दृष्टिकोण से सोचें बल्कि संपूर्ण रूप में सरकार इस बात को बता दे कि क्या हमारे लिये जरूरी है कि हम विदेशी सामान जो सस्ता हो, आर्टिफिशियल फाइबर मंगवायें या अपने कृषि उपज की जूट, रुई आदि पर ही निर्भर करें ? इन-टोटलिंग इनका असर हमारी इकानामी पर क्या होगा ? अगर मंत्री महोदय, सीमित दृष्टिकोण में, अपने मंत्रालय के दृष्टिकोण में जवाब देंगे तो बड़ा कठिन होगा क्योंकि हम तो संपूर्ण देश के रूप में सोचते हैं, एक विभाग में क्या होता है, इसी से हमारा ताल्लुक नहीं है इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि यह जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं जिन से काटन या इसी तरह की चीजें एडवर्सली एफेक्ट होती जा रही हैं इस सम्बन्ध में सरकार क्या सोचती है और यह जो सब से ज्यादा जरूरी प्रश्न बन गया है उसकी ओर मंत्री जी के स्टेटमेंट में कोई बात क्यों नहीं है।

अन्त में एक बात को फिर दोहराऊंगा कि सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार करे कि जो भी मूल्य आप निर्धारित करते हैं वह किसानों का जो सब से गरीब तबका है उसको नहीं मिल पाता है। इस बारे में आप के बयान में भी कुछ नहीं है और प्लैनिंग कमीशन की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं है और क्या आप कोई ऐसा मेथड नहीं निकाल रहे हैं कि जो किसानों का सब से गरीब तबका है उसका सामान हम कैसे उचित मूल्य पर खरीद लें और उसको राहत दें। साइंस और टेक्नोलाजी के विकास का भी ज्यादातर फायदा धनी किसान उठा लेते हैं। वह फायदा गरीब किसान नहीं उठा रहे हैं। तो इसके लिये भी सरकार सोच कर जवाब दे क्योंकि यह बात मूल्यों को प्रभावित करती है।

अपना भाषण कंक्लूड करते हुये अंत में कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन में आप किसानों को रिप्रेजेंटेशन दीजिये। किसान सभा के प्रतिनिधि वहां रहें जो अपनी बात वहां कहें। सेलेक्टेड लोग आप उसमें लेते हैं। वह उनका सही रेप्लेक्शन नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि कन्ज्यूमर्स के, ट्रेडयूनियन्स के लोग भी उसमें रहें। उनको प्राइस कमीशन में रहना चाहिये और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मूल्य फ्लक्चुयेशन्स की वजह से, दाम जो नीचे से घटा बढ़ा है उसमें किसान बर्बाद हो जाता है और उसके बाद वह कर्ज लेता है और फिर जब वह उसे अदा नहीं कर पाता तो आप उसकी जब्ती

[श्री चतुरानन मिश्र]

और कुर्की आदि करते हैं । यह अच्छी बात नहीं है ।

मैं कंक्लूड करते हुये चाहूंगा कि जो देश के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि पिछले दस वर्षों में मूल्यों के फलक्चुयेशन्स के चलते किसानों को 45 हजार करोड़ का घाटा हुआ है उसके संबंध में मंत्री महोदय को क्या कहना है यह मैं जानना चाहता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK): Shrimati Bijoya Chakravarty. Not here. Now, Mr. G. Swaminathan.

SHRI G. SWAMINATHAN: Mr. Vice-Chairman, Sir, this is my maiden speech. I am mentioning it because you may permit me to speak for a longer time than what is allowed to others.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK): But do not take too much time.

SHRI G. SWAMINATHAN: I am saying this so that others may not interrupt me by asking some questions.

Now, Sir as one who has been in the Legislature of Tamil Nadu, I have been feeling that the speeches will be more on political issues than on economic issues. But, after having come to the Rajya Sabha, during the last two or three days I have been seeing that the speeches are more on finance and economics than on political questions and, especially today, Sir, I find that from morning we have been talking of finance and administered prices and all that and now we have started talking about remunerative prices for agricultural products.

Sir, I shall be mentioning six points on this matter. The first point is that there is a wide gap between prices of agricultural products and the prices of manufactured products and it relates to what is called parity price Index Today morning, Sir, the honourable Member, Shri Kulkarni and a few other Members also have mentioned this point and the answer given by the honourable Minister is that the Government is taking into consideration, in relation to the problem of prices to be paid to the agriculturists. (1) the input prices and (2) the prices that they have to pay, the prices that they have to pay for the products which they buy outside, i.e. the Cost of Living Index. I find from the statement that the Government is fully aware of this and that they want to have parity between the prices of the agricultural products and also the prices of other products which they buy. But I find that there is no parity at all. I would like to bring to the attention of the honourable Minister that the Parity Price Index has not been maintained by the Government over a period of years. Now, Sir, it is seen from the Parity Price Index of agricultural products and the prices of manufactured products that the agricultural prices were 19.1 per cent lower during the last Plan period.

Sir. it started with a difference of 1.89 per cent between the prices of agricultural products and the prices of manufactured products when the Sixth Five Year Plan started. At the completion of the Sixth Five Year Plan a few months before, we find that the differences has gone up to 84.7 per cent. The hon. Minister would see that with such a difference, there is no parity of price index between the prices of manufactured products and the agricultural produce about which he has mentioned in the statement. The first information I have collected from the Economic Survey, 1983-84. It is given at page 138.

The second information I have collected from the statistical Survey of the Government of Tamil Nadu where it has been made clear that the price index for farmers in 1980-81 was 459.3 and the parity index of prices paid by farmers was 471.8. In the year 1983-84, the price index had risen from 667.2 while the price index for manufactured products was 933 60. While the parity index was 68.3 in 1980-81, it was 72.4 in 1983-84. It is very clear that the farmer has to be satisfied with the lower prices for the agricultural outputs and he has to purchase all his products from outside at higher prices. What is happening is that he has become

poorer and poorer everyday. It is necessary for the Government to see that they maintain some sort of parity price index between the agriculturists and those who are producing manufactured products.

Sir, the future of Indian economy relies very much on agricultural production. There has been a talk that we have enough foodgrains today and there may not be any necessity for producing more. It has been stated that the F.C.I. godowns are bursting with foodgrains. From the Seventh Five Year Plan Perspective and from the discussion on the Seventh Five Year Plan we find that we have to go in for accelerated rate of production. From 2.5 per cent growth, we may have to go in for 4 to 5 per cent growth thus almost doubling the argicultural production at the end of the Seventh Five Year Plan so as to offset the increase in population and also to see that more employment is created in the field of agriculture because agriculture alone can give 90 per cent employment while only 10 per cent employment can be given by industry. Therefore, we have to give a lot of incentive to the farmers so that they prduce more. The policy of doing anything else will not work.

The third point I would like to mention is about the Foodgrains Prices Committee of 1967. Shri L.K. Jha was the Chairman of that Committee. He is our Member now. It has been recommended by the Committee that our policy of Fair Price Shops, i.e. procuring and then distributing to the Fair Price Shops, will not go for a long time. I would like to mention for the information of the hon. Minister what Mr. L.K. Jha, the Chairman of the Foodgrains Prices Committee said. "Suppressing prices of foodgrains for distribution to Fair Price Shops will not set the problem of consumer protection as no additional supplies are available from outside and that is only withdrawing the existng supplies from the open market and distributing the same at the Fair Price Shops." I would like to give an example. Suppose a person is anaemic. There is no point in taking the blood from one hand and injecting it into the other hand. You have got to get it from ouside and inject it to the patient. On the one hand. we are procuring and creating shortage of foodgrains in the open market. We are putting it into the godowns and giving it for distribution to the Fair Price Shops. It does not solve the problem. That is not the way. The L.K. Jha Committee said that the foodgrain prices should not be on the basis of the consumer or the purchaser. But we should maintain it according to the market price. I would like to know from the Government whether the Minister will think of the foodgrain prices from the market angle instead of the consumer or agricultural angle.

Again, Sir, I may like to say that the Government has to minimize the procurement fund. I find that during the Seventh Plan, the Government has to spend nearly Rs. 7,200 crores for procurement. And a lot of money has to be spent on handling further production of foodgrains and also for high handling coss, loss of interest and withdrawal of resources. I wish to ask whether the Government will think of an alternative policy so that the money now being spent so much on these foodgrains purchases can be more usefully spent in creating infrastructure for more production like irrigation, etc. so that the money can be well-spent and we can think of a market economy which may give a better price to the farmers. The Government also has to consider paying difference between the market price and the floor price. Sir, there had been a discussion. The prices of the agricultural products cannot be constant. Sometimes they are high and sometimes they are low. When it is low, the Government has to give support price for these foodgrains. It is not necessary for the Goernment to go and procure the foodgrains whenever the price is low. It may be enough it the Government gets into the market. and if the market price is not sufficient and it is low, it is enough if the Government gives the difference in support prices. This is

[SHRI G. Swaminathan]

what is being done in other countries. If we do that, most probably, our funds may not be locked up to this extent.

Finally, Sir, the hon. Minister for Finance announced earlier that he would be announcing a long-term farm policy. He said it in the budget. Now I find that he is going to give us an administered prices policy. I would also like to know from the hon. Minister as to when the Government will announce the long-term farm policy as informed by the Finance Minister in his Budget Speech so as to end the uncertainities in this sector.

Finally, Sir, I would like to ask these questions from the hon. Minister: (1) Is the Government aware that there is a wide gap between the prices of agricultural products and prices of manufactured products and if so will the Government maintain parity? (2) Is the Government aware that the future of the Indian economy very heavily relies on the substantial increase in the production of foodgrains and will they give incentives to the farmers? (3) Is the Government aware of the recommendations of the Food Prices Commission of 1967 which said that the Government should think of a market-oriented policy on foodgrains rather than consumer-oriented or producer-oriented policy? (4) Is the Government aware that it is in an impossible situation to invest Rs. 7,200 crores and would they like to divert this money to have infrastructure for more production like irrigation, etc.? (5) Will the Government think of paying only the difference in prices whenever the market price is lower? (6) When the Government is going to announce a long-term farm policy as informed by the Finance Minister earlier? Thank you, Sir.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, I want to say only one point that there should be one standard price of the essential commodities of the foodstuff throughout the country. I want to cite an example in this connection of Assam. When the price of say, potato here in Delhi is Rs.2, it is Rs. 7 in Assam. In the other eastern parts of the country like Meghalaya.. (*Interruptions*) . . .

AN HON. MEMBER: In Delhi it is Rs. 4.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK): Don't interrupt her.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: When it was Rs. 2 here, it was selling at Rs. 7 in Assam. Sir, I want to say that if one standard, stable price is maintained throughout the country, this trouble would not arise. Whether it is kerosene or rice or coconut or anything, there is a staggering price in the eastern sector. So, I request that the communications system should be developed, the transport system should be developed and the prices should be fixed and, I think, then only the prices can be controlled. Thank you, Sir.

*SHRI DEBENDRA NATH BARMAN (West Bengal): Hon. Mr. Vice-Chairman, Sir, the economy of our country mainly depends upon agriculture. Majority population of our country are farmers and they are also very poor. Unless we improve the economic condition of farmers, we cannot improve their purchasing power. Consequently, the domestic market for industrial goods cannot also be widened. But the agricultural system in our country is based on feudalism. That system encourages profiteering and exploitation. Our farmers are subject to exploitation both ways. On the one hand they are compelled to sell their produce at lower prices and on the other, they purchase their daily necessities of life at higher prices. Consequently, the condition of farmers deterriorates day by day.

Sir, today we are discussing about the remunerative prices for paddy, wheat and sugarcane. Many Hon. Members have

*English translations of original speech delivered in Bengali.

observed that the cost of production for these agricultural commodities has risen. It is a fact that the prices of chemical fertilizers, pesticides, diesel and agricultural implements have increased. The charges for electricity have also gone up. So is the case of labour costs. But the price of agricultural produce has not been increased in keeping with the rise in prices of agricultural inputs. As we know, the prices of agricultural inputs have risen by ten to fifteen per cent. It seems that the Government does not have a firm policy for controlling the prices of agricultural inputs. Similarly, the policy of the Government in regard to the role of J.C.I., C.C.I. and F.C.I. is very unsatisfactory. J.C.I. is there to purchase jute from the growers. But the Agricultural Price Commission does not fix the remunerative price of jute on the basis of its cost of production as this body does not have any idea about it. when there is surplus production of jute, J.C.I. cannot purchase whole of it. They just purchase 15 per cent to 20 per cent of entire stock. Similarly F.C.I. cannot purchase the entire stock of wheat from the farmers. Thus, farmers in distress are forced to sell their produce at lower prices to middlemen and moneylanders. Similar condition prevails in regard to cotton and sugarcane. The role of C.C.I. is not satisfactory in regard to the purchase of cotton. The sale of these agricultural commodities is at the mercy of factory owners. They purchase them at lower prices. It is seen that the prices of these commodities are more in the open market than the prices fixed for them by the Government. When there is surplus production of agricultural commodities, the prices go down naturally. Again, when there is shortage of production, the prices go up. This is the order of agricultural prices.

Sir, producers of agricultural commodities are also buyers of industrial goods. Sugarcane growers are buyers of sugar. It is a fact that growers of agricultural commodities purchase their consumer goods at a price more than the price of their own produce. Consequently, their poverty is growing day by day and, ultimately, they turn into landless agricultural labourers.

The farmers are not being paid remunerative prices for their produce. They are even unable to realise the cost of production of their produce. The fact is that the Government does not have a correct policy on the price situation. Consequently, the prices of consumer goods are allowed to go up exhorbitantly. With the erosion of money value, the prices of industrial goods are going up day by day. But the Government has not yet framed a stable policy for providing remunerative prices for agricultural commodities. In 1980-81, the price of sugarcane was Rs. 23 to 26 per quintal in the open market. But in 1982-83 that price came down to Rs. 15 per quintal. At that time the Sugar Mill owners locked up Rs. 250 to 430 crores as they did not pay dues of sugarcane growers. But in 1980-81 the Government fixed the price of sugarcane at Rs. 13 per quintal when the open market price was Rs. 23 to 26 per quintal. In 1984-85 the Government fixed the price oof sugarcane at Rs. 14 per quintal.

[The Vice-Chairman (Shri Pawan Kumar Bansal) in the Chair].

So the Government increased the price of sugarcane by only 8 per cent. But what price the Government fixed for sugar? In 1980-81, the price of sugar in the month of November was Rs. 2.85 per Kg. That amount was increased by the Government to Rs. 4.40 per Kg. So the increase was upo 54.3 per cent. This shows how the sugar Mill owners are earning profits. Open market prices of sugar were more than the ex-factory prices by Rs. 20 to 35. But the sugarcane growers did not get reasonable price for their produce. Whenever farmers do not get remunerative prices for their produce, they turn to the production of alternaiive crops. Consequently, the production of jute, sugarcane, mustard seeds and wheat come down and the Government is compelled to import sugar, edible oil and wheat at higher prices. This leads to the drainage of our precious foreign exchange. The prices of these commodities also rise in our country in natural course. So the Government must have a policy towards

[Shri Debendra Nath Barman]

maintaining parity in prices between agricultural goods and industrial goods. This policy will enable the farmers to purchase consumer goods without incurring losses for their agricultural goods.

Wholesale trade should be under the control of the Government. There should be a fixed price for all essential commodities. Fifteen to sixteen items of essential commodities should be distributed through Public Distribution system at the same price throughout the country. It will regulate the prices of essential commodities in the market. For want of a firm policy to this effect, the profiteers, blackmarketeers, hoarders, middlemen, Mill owners, smugglers and moneylenders are enjoying the fruits of the labour of farmers. Again the farmers are compelled to purchase their essential commodities at higher prices from the profiteers and blackmarketeers. In this manner, the working class is being exploited out and out. So the Government is allowing the hoarders, profiteers, blackmarketeers to earn huge profits at the cost of poor farmers. This has been possible because of the wrong attitude of the Government. I feel that the Government is safeguarding the interests of a particular class. I would, therefore, request the Hon. Minister to formulate a correct policy on agricultural prices in the interests of poor farmers so that they may not be deprived of remunerative prices for their produce. With these words, I conclude.

Thank you.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Mr. Vice-Chairman, the necessity of remunerative prices has been amply demonstrated and shown by various statistics presented by Shri Kalpnath Rai and other speakers. The hon. Minister in his statement has stated:

"The cost of production data which are made use of by the Commission are based on comprehensive countrywide studies carried out mostly by agricultural univertities in accordance with the conceptes, methodology and sampling design worked out by experts.

Inarriving at cost of production estimates, full account is taken of the value of all inputs, such as, human labour, both hired and family bullock labour, seeds, fertilisers, insecticides, machine labour irrigation etc. The cost estimates also take into account depreciation on implements. . ."

These are the inputs, as per the statement of the hon. Minister, which are being taken into consideration. But Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to make a very great revelation today. I will show you how the agriculturists are being taken for a ride. Our hon. Minister, Shri Dhillon, comes from Punjab, which is a wheat-growing area. (Interruption) I put a Starred Question the other day but, unfortunately, it could not come up for discussion. It was slated for 31st July, 1986. Mr. Kalp Nath Rai, please listen to this. I had asked 'Will the hon. Minister of Food and Civil Supplies be pleased to state: (a) the procurement rate of wheat and the issue rate of wheat to flour mills by the Food Corporation of India in December, 1985 and (b) the procurement rate of wheat and the issue rate tion of India as on 1st Feburary and 1st April- 1986'. The answer is 'A statement of wheat to flour mills by Food Corpera- is laid on the Table of the House'. What is that statement? It is very extraordinary. The procurement price of wheat, the price which is paid to the farmers, as on December, 1985, was Rs. 157, and the issue price of wheat to roller flour mills, as on December, 1985, was Rs. 172. The difference is Rs. 15 between the procurement price of wheat and the issue price of wheat to flour mills. This is understandable Come to the latter part of it. As on 1st February, 1986, the procurement price of wheat stood at Rs. 157, the same as it was before. You paid to the farmers only Rs. 157. But the issue price of wheat to the flour mills was Rs. 190, the difference was of the order of Rs. 33. Now, there is a glaring example. As on 1st April, 1986, the procurement price of wheat stood at Rs. 162. Mr. Vice-Chairman, Sir, as against this price, Rs. 162, which means, the increase was just Rs. 5 from the December, 1985, level, the issue price of wheat to

flour mills was Rs. 220, a difference of almost Rs. 60.

SHRI KALPNATH RAI: More than Rs. 60.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: I would ask the hon. Minister: what has he to say about this? On the one hand the price you pay to the poor farmer is only Rs. 157, whereas in the case of the flour mills, the issue price is Rs. 220. There is a reason why I have raised this question. There is a lobby of the flour mills in the wheat-growing areas from his place working here to compel the Food Corporation of India to issue wheat at a higher rate so that they can take advantage of the slump in the market in the wheat-growing areas and buy wheat at a lower rate. In the areas, where the flour mills have very little choice but to take from the Food Corporation of India, they have to take at Rs. 220, but here, they can buy at Rs. 157 only. This thing has to be taken care of. This is a very sinister way. I would request the hon. Minister to kindly take into consideration this aspect and tell us about this.

The other point I want to make is, now, we have stocks in Punjab. I heard in the BBC this morning that American Government is supplying wheat, a substantial quantity of wheat, to Russia at a lower price, at a subsidised price. If you have got enough stocks and since we are buying a lot of things from Russia, they are our friends, would not the Government of India also take into consideration the export of wheat to Soviet Union so that our stocks are lower and we are in a position to give an increased price to our farmers?

श्री राम चन्द्र विकल : उपसभापति जी, कृषि मूल्य आयोग से किसानों को उचित दाम मिले, इस सवाल पर आज सुबह से बहस हुई है । वैसे तो इस सवाल पर सदन में बहस हो. इस पर काफी विवाद रहा, फिर भी कल्पनाथ राय जी ने, महाजन जी ने और वीरेन्द्र वर्मा तथा हजारे मिश्र जी ने तो बहुत आंकड़े पेश किये हैं । मैं आंकड़ों के विषय में तो नहीं जाऊंगा इस वक्त, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस देश का दुर्भाग्य यह है कि यहां मजदूरों से मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति दिनों-दिन बढ़ती जा रही है । मरीज बहुत भयंकर बीमार हो जाए, तो डाक्टर की फीस बढ़ जाती है । जब मजबूरी होती है, मरीज मौत के मुंह में जाने को हो, तो उस डाक्टर की फीस बढ़ जाएगी । जब अकाल पड़ जाएगा इस देश में, तो व्यापारियों के दाम बढ़ जायेंगे एकदम, जब कोई आंदोलन हो जाएगा और उससे कुछ बात हो जाएगी तो फिर हम मानने को तैयार हो जाते हैं एकदम । मजबूरी कहीं भी हो जाए, तब हम बात मानते हैं, उसमें पहले मानने को तैयार नहीं होते हैं । किसान जो इस देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है एक तौर से, किसान के बिना इस देश का आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता, यह कृषि प्रधान देश भी कहलाता है, लेकिन किसान की जो समस्याएं और कठिनाइयां हैं और किसान को पैदावार के जो मूल्य हैं, वह उसको नहीं मिल पा रहे हैं । किसान की मजबूरी को भी यह सरकार समझती है कि यह कोई आंदोलन नहीं कर पा रहा है क्योंकि जब मजदूर आंदोलन करता है, तो उसका असर तो उद्योगपति या कारखाने वालों पर पड़ता है । सरकारी कर्मचारी जब आंदोलन करते हैं, तो उसका सरकार पर या जनता पर असर पड़ता है, उन पर असर पड़ता ही नहीं । किसान यदि कोई हड़ताल या आंदोलन करता है, तो उसका असर डाइरेक्ट लौट कर किसान पर पड़ता है। लिहाजा वह कोई आंदोलन या हड़ताल नहीं करता । किसान की इस मजबूरी को भी सरकार जानती है । इसीलिए किसानों की आवाज और खास कर उसकी पैदावार के उचित दाम नहीं मिल पाते हैं ।

लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधान मंत्री थे, तो देश में अन्न का महान संकट था । उन दिनों हमको विदेशों से अन्न मंगवाना पड़ रहा था । उस समय दुर्भाग्यवश हमारे देश पर पाकिस्तान का हमला भी हो गया । शास्त्री जी ने उन दिनों नारा लगाया था "जय किसान

[श्री रा चन्द्र विकल]

जय जवान"। मैं शास्त्री जी को भी एक बात कहता था और कई बार कहा कि केवल जय किसान कर दें, जय जवान तो अपने आप हो जाएगा। किसान की जो सामग्री है, उसको खाकर जवान भी बनते हैं। मगर किसान की जो दिक्कत है, उसको अभी तक हल नहीं किया गया है। किसान खेती का हिसाब नहीं रखते। उपसभाध्यक्ष जी, उसका परिवार तो सारा खेत में रहता है, सर्दी में, गर्मी में, ओले में, पाले में, उसका कोई हिसाब नहीं है। सारा परिवार लगा रहता है, खुद भी वह लगा रहता है, उसके मवेशी भी काम करते रहते हैं। सब को अगर मेहनत लगाई जाए और फिर उसका मुनाफा लगाया जाए, तो मैं समझता हूं कि किसान को... (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : एक रुपया नहीं मिलता।... (व्यवधान)

श्री राम चन्द्र विकल : ...और यही वजह है कि आज किसान की दुर्दशा सब से ज्यादा है।

एक माननीय सदस्य : मर गया है वह तो।

श्री राम चन्द्र विकल : जो सरकारी नौकरी में चपरासी है, उसकी हालत किसान से कहीं अच्छी है।

श्री कल्पनाथ राय : सही बात है, चपरासी बढ़िया है।

श्री राम चन्द्र विकल : यहां भूमि सुधार के माने जमीन बंटवारे के अलावा कुछ समझा नहीं जाता, जहां तक मैं समझता हूं आज तक। जमीन के बंटवारे को--यही भूमि सुधार समझा जा रहा है। कैसे पैदावार बढ़ायें, कैसे किसान को उत्साहित किया जाए, किसानों की आर्थिक कठिनाइयों को कैसे हल किया जाए, यूं तो कृषि के क्षेत्र में दिनों-दिन नये विज्ञान और नये बीज भी आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह कृषि सुधार होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। यह एग्रीकल्चरल, कास्ट एण्ड प्राईस कमीशन जिसके ऊपर जोर देकर हमारे कल्पनाथ राय जी ने कहा, अन्य मेम्बरों ने भी कहा, यह बात सच है कि बूटा सिंह जी ने यहां हमारे सामने बैठ कर वायदा किया था कि एक महीने भर में इसकी घोषणा करदेंगे, लेकिन वह भी अभी तक नहीं हो सकी। मैं कृषि मंत्री जी से चाहूंगा कि उसकी घोषणा स्पष्ट कर दें कि बनाना है या नहीं। संदेह में रखना ठीक नहीं है। कम से कम हम जबूरी तो जान लें। जो कहा गया है कम से कम उसको तो करना चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं देश का दुर्भाग्य और भी यह मानता हूं कि क्षेत्रवाद या प्रांतवाद और बहुत सी समस्यायें उठी हुई हैं और छोटे दायरे में कभी उठ भी जाती हैं। चाहे हम वोट के लोभ से उठा दें या किसी और लोभ से। जब हमारे देश में कहीं अकाल पड़ता है और जब किसान की पैदावार हो तो उस पैदावार को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी जाती है। यह भी देश की एकता को एक खतरा है। अब हमारे यहां गुड़ पैदा होता। दिल्ली में न आये उस पर सीमा लगा देते हैं। होता क्या है कि चोरी-चोरी वह सब आ जायेगा, रिश्वत देकर आ जाएगा और आने से नहीं रुकेगा। इस तरह किसान को मार दिया जाता है। जब उसकी पैदावार होती है तो उस पर सीमा लगा देंगे। मद्रास में अकाल पड़ा है। वे लोग परेशान हैं। उनको चीज नहीं मिल रही हैं। जिस किसान की पैदावार है वह डायरेक्ट मद्रास में भेजने में असमर्थ है क्योंकि राज्य की सीमा लग गई। किसान के मुनाफे के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जाता। पैदावार तभी बढ़ेगी जब किसान को लागत मूल्य मिलेगा जब उसकी मेहनत का उसे मूल्य मिलेगा तभी मैं समझता हूं कि किसान ज्यादा पैदावार बढ़ायेगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, किसान से अधिक मुनाफा जगह बदलने वाला व्यापारी प्राप्त करता है बल्कि वह हजारों गुना में करता है। यहां से लेकर वहां

भेजेगा, वहां से वहां भेजेगा। उसको मुनाफा ज्यादा है। या फिर उस उद्योगपति को मुनाफा ज्यादा है जो किसान की चीजों की शकल बदलता है। इस प्रकार उद्योगपति जो शकल बदलता है उसको मुनाफा ज्यादा है और व्यापारी जो किसान की चीज की जगह बदलता है वह ज्यादा मुनाफा कमाता है। किसान पैदा करने वाला मुनाफा ज्यादा नहीं कमाता है। मैं कृषि मंत्री जी से जो स्वयं किसान हैं उनसे मुझे बड़ी आशा है और पंजाब से आये हुए हैं और पंजाब तो हमारे देश को प्रेरणा देता रहा है, उनसे आशा करूंगा कि वे किसानों की कठिनाइयों के जितने सवाल हैं उनके समाधान के लिए उचित मूल्य दिला सकें और जो आयोग बनाने की घोषणा हुई है उसके अनुसार आयोग गठित करें साथ ही यह बात सच है कि उसमें किसानों के प्रतिनिधि अधिक होने चाहिए। यदि उनकी तादाद अधिक होगी तो सुझाव अच्छे मिलेंगे। मानना, न मानना वह तो आपकी बात है। फिर भी मैं कहूंगा कि जो आयोग बनाया जाए उसमें उनकी जो उचित बात उसको माना जाए। आयोग भी कभी-कभी ऐसी बात कर देते हैं जो नहीं करनी होती है। आयोग को करना तो होता नहीं सरकार को ही करना पड़ता है। मैं उस कठिनाई को जानता हूं। लेकिन किसान की जो उचित बात हो उसको जरूर माना जाना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ आपका आभार मानता हूं और कृषि मंत्री जी से आशा करता हूं कि किसानों को वह उचित मूल्य दिलायेंगे। चाहे वह इसे आयोग बनाकर करें या किसी और तरह करें। किसान की समस्या उसकी अपनी समस्या ही नहीं है वह एक राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए राष्ट्रीय समस्या समझकर ही किसान की समस्या का अध्ययन करना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपका फिर धन्यवाद करता हूं।

श्री राम अवधेश सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। जहां तक किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलने का सवाल है उसका कारण बिल्कुल साफ और एक शब्द में यह है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। क्योंकि कोई भी काम नीयत से, नीति से और नेता से होता है। नीयत जब तक साफ नहीं होगी तब तक काम नहीं हो सकता है। नीयत बनती है उसके भीतर के संबंधों से भीतर का संबंध किन से है? जो किसान हैं उनसे उनको तो पैसे मिलते नहीं हैं, चुनाव के चंदे मिलते नहीं हैं। मोटी-मोटी राशि मिल सकती है इंडस्ट्रियल लोगों से जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं वे पैसे देते हैं। कृषि में जो इनपुट्स हैं, खाद है, कीटनाशक औषधि है ये सारी चीजें जो यंत्र बनाते हैं, ट्रैक्टर बनाते हैं और ये पूंजीपति लोग बनाते हैं उनसे तो इनको पैसे मिलते हैं इसलिए वह उनके सामान महंगे जरूर करेंगे ताकि उनको मुनाफा मिले। लेकिन किसान को अपनी उपज के उचित दाम नहीं मिल पाते। अभी जब आलू पैदा हुआ तो मुश्किल से आठ आना किलो ही बाजार में बिका। इस समय चार रुपये मिनिमम है और सात-आठ रुपये तक है। जब हम लोगों के जमाने में प्याज पांच रुपये किलो हो गया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर गांव-गांव का कांग्रेसी वर्कर सिर्फ यही चिल्लाता था, सब कुछ छोड़कर सिर्फ प्याज-प्याज ही बोलता था। लेकिन आज इनको शर्म भी नहीं आती है कि 50 पैसे किलो आलू खरीदवाया व्यापारी को और फिर उन्हीं से चार रुपये, पांच रुपये सात रुपये आलू बिकवा रहे हैं। मुझको एक आदमी ने बताया एक व्यापारी ने बताया कि चार महीने पहले हम लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपया लगाकर और सब आलू खरीदकर बंद कर दिया। तो एक आदमी ने उससे पूछा कि आलू तो सड़ जाएगा, आलू क्यों खरीद रहे हो? तो उसने कहा कि इस आलू से बाद में इतना फायदा होगा कि मैं आगे चलकर बताऊंगा। उसने कहा कि जितना आलू सड़ेगा उतना ही हम लोगों को फोयदा होगा। अगर आलू सड़ जाएगा तो सात, आठ दस रुपये बिकवा देंगे। इस प्रकार आलू तो खरीदकर जमा कर दिया। मैं चुनौती

[श्री राम अवधेश सिंह]

के साथ सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार में हिम्मत है कि जो आलू जब्त कर दिया गया है, जो आलू छिपा दिया गया है उसको वह बाहर निकलवाये ? क्या यह सरकार कर सकती है ? जो आलू उस समय पचास पैसे किलो बिकता था आज वह सात रुपये दस रुपये के भाव से बिक रहा है । क्या कृषि मंत्री जी को उसमें से कुछ हिस्सा मिला है उन व्यापारियों से ? अगर मिला न, कितना मिला है, बताइये ?

श्री रफीक आलम (बिहार): उपाभाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । लेकिन वक्त की पाबंदी कर दी । मैं सिर्फ कुछेक बातें ही कहना चाहूंगा । कम से कम हमारे विरोधी दल के लोग काश्तकारों के मामले को पोलिटीकल नहीं बनाएं । काश्तकार लोग आज बहुत परेशान हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है । महात्मा गांधी जी ने कहा था, इंडिया लिवज इन दी विलेजज और जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो इन्हीं काश्तकारों ने महात्मा गांधी जी का साथ दिया था और अंग्रेजों को यहां से निकाला था । लेकिन आज काश्तकार के साथ सब से बड़ा प्राब्लम यह है कि वह जो पैदा करते हैं उसकी कीमतें कम है और जो कुछ वे मार्किट से खरीदते हैं अपनी ही चीजें सिर्फ उनकी शक्ल बदल दी गई है. उसकी कीमतें ज्यादा हैं ।... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : आप सरकार में हैं ।

श्री रफीक आलम : ये सारी प्राब्लम्ज आप लोग क्रिएट करते हैं और बदनाम करते हैं हमको । काश्तकारों के सामने सब से बड़ी प्राब्लम यही है कि जो मैनुफैकचर्ड गुड्स खरीदते हैं चाहे वे मिल की हों या कहीं और की उनकी कीमतें ज्यादा हैं और जो वह स्वयं पैदा करते हैं उनकी कीमतें कम हैं । चाहे जूट का मामला हो, चाहे कपास का मामला हो, चाहे गेहूं का मामला हो, चाहे गन्ने का मामला हो या और कोई चीज का मामला हो । उपसभाध्यक्ष जी, आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि 1984 में जूट पैदा करने वालों को मिला चार सौ रुपये मन, एक हजार रुपये क्विंटल फिर उसी जूट पैदा करने वाले को 60 रुपये मन मिला यानी अब कहां चार सौ रूपये मन और कहां साठ रुपये मन । लेकिन वही चीज जब मिल वाले देते हैं तो उसमें कोई कमी नहीं । इसलिए अभी सरकार से मेरी गुजारिश है और यह भी बात है कि हमारे वोटर्ज भी जितने हैं, हम लोग भी आते हैं चाहे एम पीज या एम एल एज होकर आये हैं ज्यादातर काश्तकार के ही नुमायंदे हैं, इसलिए हर आदमी का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह गांव की तरफ देखे । क्योंकि जब गांव खुशहाल होगा तभी मुल्क खुशहाल हो सकता है । गांव गरीब होगा तो मुल्क शक्तिशाली नहीं हो सकता है क्योंकि सब से ज्यादा प्राड्यूसज तो वही हैं और सब से ज्यादा कंजयूमर वही हैं । अभी बिकल जी ने यही कहा है कि एक चपड़ासी जो है वह अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे सकता है, उन्हें खिला सकता है, लेकिन काश्तकार इतना भी नहीं कर सकता है । पलड से परेशान हो तो वह, ड्राउट से परेशान हो तो, कीमतें बढ़ें तो काश्तकार परेशान हो, हर सूरत में परेशान काश्तकार ही होता है । इसलिए मैंने कहा कि चाहे ब्यूरोक्रैट्स हों, चाहे राजनीतिज्ञ हों, चाहे बिजनैसमैन हों आजादी की रोशनी तो इन सब के घरों में पहुंची है, लेकिन अभी तक यही आजादी की रोशनी काश्तकार के घर तक नहीं पहुंची है । अभी तक काश्तकार की हालत वहीं की वही है जो कि पहले थी । उसकी हालत बिल्कुल बतदतर होती जा रही है । इसलिए मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कहूंगा कि जब भी आप प्राइस फिक्सेशन करें तो काश्तकारों के प्रतिनिधि को जरुर रखें । यह नहीं है कि जो जूट नहीं जानता है कि जूट कैसा होता है वह जूट की प्राइस फिक्स करे । पूछते भी नहीं कि इसकी लागत क्या है । मैं भी जूट पैदा करने वाला हूं, एक मन जूट पैदा करने में लगभग 200 रुपया खर्च हो जाता है ।

यह फारेन एक्सचेंज लाता है, गोल्डन फाइबर कहलाता है । आज किसान की हालत बहुत खराब है उसको बहुत प्राब्लम हो रही है । अगर किसान आन्दोलन पर उतर आयेंगे तो कोई ताकत उसको रोक नहीं सकेगी । इसलिए यह आंदोलन होने के पहले मैं सरकार से अपील करूंगा कि किसानों की तरफ वह ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, वे जो चीजें पैदा करते हैं उनकी जायज कीमत उन्हें मिले और ये जो बीच में नफाखोरी करने वाले है इन पर पाबंदी लगे । ऐसी बात न हो कि जो पैदा करता है वह भूखा रहे और जो चीज को सिर्फ इस मार्कीट से उस मार्किट तक पहुंचा देता है वह पक्के मकान में रहे और वहां पर बिजली का पंखा भी चलता हो । मुझे व्यापारियों से शिकायत नही है, शिकायत मुझे यह है कि जो पैदा करते हैं उनको कम मिलता है जबकि उनको ज्यादा मिलना चाहिए । जो यहां की चीजें वहां ले जाते है उनको कम मिलना चाहिए । इस सूरत में आप ऐसा लैवल लायें कि समाज में हम अमनो-अमान से रहें, मुल्क खुशहाल रहे और हमारा तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे । धन्यवाद ।

†[आशरी रफीक आलम (बिहार) : सभापति महोदय जी - मैं आप का आभारी हूं - कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया - लेकिन वक्त की पाबंदी करदी - मैं सिर्फ कुछ एक बातें ही कहना चाहूंगा - कम से कम हमारे वरुदधी दल के लोग किसानों के मामले को पोलिटिक्स नहीं बनाएं - किसान लोग आज बहुत परेशान हैं - इस से कोई इंकार नहीं कर सकता है - महात्मा गांधी जी ने कहा था - "दांडी यात्रा ऐज दी वैलिज" - और जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

तो इन्हीं किसानों ने महात्मा गांधी जी का साथ दिया था और अंग्रेजों को यहां से निकाला था - लेकिन आज किसानों के साथ सब से बड़ा प्राब्लम यह है कि वह जो पैदा करते हैं उस की कीमतें कम हैं - और जो कुछ वह मार्केट से खरीदते हैं - अपनी ही चीजें सिर्फ उन की शक्ल बदल दी गई है - उसकी कीमतें ज़्यादा हैं ... "مداخلت"

ایک معزز ممبر : آپ سرکار میں ہیں -

شری رفیق عالم : یہ ساری پرابلمس آپ لوگ کریئٹ کرتے ہیں - اور بدنام کرتے ہیں ہمکو - کسانوں کے سامنے سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ جو مینوفیکچرڈ گڈس خریدتے ہیں - چاہے وہ مل کی ہوں یا کپڑوں اور کی ان کی قیمتیں زیادہ ہیں - اور جو وہ سویم پیدا کرتے ہیں - ان کی قیمتیں کم ہیں - چاہے جوٹ کا معاملہ ہو - چاہے کپاس کا معاملہ ہو - چاہے گنے کا معاملہ ہو - چاہے گیہوں کا معاملہ ہو - یا اور کوئی چیز کا معاملہ ہو - اب سبھا ادھیکش جی - آپ کو یہ سنکر تعجب ہوگا - یہ ۱۹۸۴ میں جوٹ پیدا کرنے والوں کو ۴ چار سو روپیہ من - ایک ہزار روپیہ کوئنٹل پھر اس جوٹ پیدا کرنے والے کے ساتھ روپیہ ہی ملا - اب بتائی کہاں چلا

[شری رفیق عالم]

نہیں پہنچی ہے- ابھی کاشتکاروں کی حالت وہی کی وہی ہے جو کہ پہلے تھی - اس کی حالت بالکل بدتر ہوتی جارہی ہے- اس لئے میں ایگریکلچر منسٹر سے کہونگا کہ جب بھی آپ پرائس فکسیشن کریں - تو کاشتکاروں کے نمائندہ کو ضرور رکھیں - یہ نہیں کہ جو جوٹ نہیں جانتا وہ جوٹ کیسا ہوتا ہے- وہ جوٹ کی پرائس فکس کرے- پوچھتے بھی نہیں - کہ اسکی لاگت کیا ہے - میں بھی جوٹ پیدا کرنے والا ہوں - ایک من جوٹ پیدا کرنے میں لگ بھگ دو سو روپیہ خرچ ہو جاتا ہے - یہ فارن ایکسچینج لاتا ہے - گولڈن فائبر کہلاتا ہے - آج کسان کی حالت بہت خراب ہے - اسکو بہت پرابلم ہو رہی ہے - اگر کسان آندولن پر اتر آئینگے - تو کوئی طاقت اسکو روک نہیں سکیگی - اسلئے یہ آندولن ہونے کے پہلے میں سرکار سے اپیل کرونگا - کہ کسانوں کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان دے - وہ جو چیزیں پیدا کرتے ہیں انکی جائز قیمت انہیں ملے- اور جو یہ بیچ میں نفع خوری کرنے والے ہیں ان پر پابندی لگے - ایسی بات نہ ہو کہ جو پیدا کرتا ہے - وہ تو بھوکا رہے - اور اسکی چیز کو صرف اس مارکیٹ سے اس مارکیٹ تک پہنچا دیتا ہے - وہ بیچ میں رہے - اور وہاں پر سو روپیہ من اور کہاں ساٹھ روپیہ من - لیکن وہی چیز جب مل والے دیتے ہیں تو اس میں کوئی کمی نہیں - اس لئے ابھی سرکار سے میری گزارش ہے- اور یہ بھی بات ہے کہ ہمارے ووٹرز جیتے بھی ہیں - ہم لوگ بھی آتے ہیں - چاہے ایم پیز - یا ایم - ایل - ایز - ہوکر آئیں - زیادہ تو کاشکاروں کے ہی نمائندہ ہیں - اس لئے ہر آدمی کا یہ کرتویہ ہوتا ہے- کہ وہ گاؤں کی طرف دیکھے- کیونکہ جب گاؤں خوشحال ہوگا - تبھی ملک خوشحال ہوگا - گاؤں غریب ہوگا تو ملک شکتیشال نہیں ہو سکتا ہے- کیونکہ سب سے زیادہ پروڈیوسرز تو وہی ہیں - اور سب سے زیادہ کنزیومرز وہی ہیں - ابھی وکل جی نے شعیب کہا ہے- کہ ایک چپڑاسی اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دے سکتا ہے- انہیں کھلا سکتا ہے- لیکن کاشتکار اتنا بھی نہیں کہیں کرسکتا ہے- فلڈ سے پریشان ہو تو وہ - ڈراؤٹ سے پریشان ہو تو وہ - قیمتیں بڑھیں تو کاشتکار پریشان ہوں - ہر صورت میں - پریشان کاشتکار ہی ہوتا ہے- اس لئے میں نے کہا کہ چاہے بھوروکریٹس ہوں - چاہے بزنیس مین ہو - آزادی کی روشنی تو ان سب کے گھروں میں پہنچی ہے- لیکن ابھی تک یہ آزادی کی روشنی کاشتکاروں کے گھر تک

بجلی کا پلکھا چلتا ہو - مجھے
بدوپاریوں سے شکایت نہیں ہے -
شکایت مجھے یہ ہے کہ جو پیدا
کرتا ہے - انکو کم ملتا ہے - جبکہ
انکو زیادہ ملنا چاہئے - اس صورت
میں آپ ایسا لیول لائیں کہ سماج
میں امن و امان رہے - ملک
خوشحال رہے اور ہمارا ترنگا جھنڈا
ہمیشہ اونچا رہے - شکریہ -]

SHRI G. S. DHILLON: Mr. Vice-Chairman, Sir, I have heard the points of view of the Members from all the sections of the House.

One thing that I am quite happy to see is that they have evinced very keen interest in agriculture.

In my parliamentary life I had not seen a calling-attention sponsored by 65 Members. That shows how much the House is concerned about it.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Last time also it was like that.

SHRI G. S. DHILLON: Though I could not count 65 Members present here, those who spoke have brought out all kinds of suggestions and criticism. The Call Attention, as I saw, was so innocent that it was just a concern of the Members on the remunerative prices on the agricultural produce, particularly paddy, wheat and sugarcane. In my own way I had given a pointed answer. I think that was quite indicative of the nature the points that were to be raised on the working of the Agricultural costs and Prices Commission. Some questions that have been asked relate to the Ministry of Agriculture and there are some others which are beyond its scope and jurisdiction. Some of them relate to the Ministry of Food and Civil Supplies or Industries, but they were all linked together. As I told you the agricultural prices are fixed keeping in view that the prices so fixed will not only determine the minimum or support prices, but as a matter of our declared policy the fact that the remunerative prices should be such that they should be remunerative to the farmers in the real sense I do not mean remunerative price should be so high as to his other interests. While determining such cost of production, we take into consideration so many factors. There is a long list, but I give here only a few of them like seeds, fertilisers, diesel, electricity, implements, land, whether leased or owned, labour, whether family labour or hired labour and so many other factors. The likely effect of the price policy on the rest of the economy, particularly on the cost of living, level of wages and industrial cost structure is also taken note of.

Shri Kalpnath Rai and some other Members said that in spite of the promise made by my predecessor there has been no proper Agricultural Costs and Prices Commission constituted and in its absence how could there be the prices fixed? May I tell to those Members that the CACP is a continuing body that existed and that still is existing. The question at present before us is how to increase the membership of some non-official representatives of the farmers. I agree with the hon. Members on the question of association of the non-official members with this body, particularly the representatives of farmers' interests whether they represent the dryland interest or those of edible oil or cereal crops or horticulture or the interests or in whatever field they work. We will have to associate them at one stage or the other so that the opinion of that section is reflected in the determination of that price which the Commission fixes. At present the Commission consists of a Chairman, Members Secretary, one Member Official and one non-official member—four of them. We want to see if there could be seven. We have already moved in the matter and we have almost completed the task. I think we will be announcing the acceptance of our proposal and names of those members. While determining the prices, I must say, when you relate them to the industry or the finished product or the processed product, I wish I could do it myself, but the structure and system of the Government is such that, my Department is

[Shri G. S. Dhillon]

concerned only with producing. I may produce wheat. I may produce paddy. These items go to the Food Corporation of India. It is not under me. Some hon. Members have brought into this debate all sorts of general issues whereas this Calling Attention relates to the remunerative prices for the agricultural produce particulraly for paddy, wheat and sugarcane.

श्री राम अवधेश सिंह : श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मंत्री जी ने यह कहा है कि हमारे मंत्रालय का संबंध केवल प्रोडक्शन से है चाहे पैडी हो, जूट हो, आलू हो, उसकी प्राइस से बिक्री से संबंध नहीं है। जो प्राइज के संबंध में बहस चल रही है यह बात उसमें कवर होती है एग्रिकल्चर प्राइस के तमाम फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं.....

उपसभाध्यक्ष (श्री पवन कुमार बांसल) : उनको आपने ठीक से सुना होगा तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा...

श्री राम अवधेश सिंह : कालिंग एटेंशन में मंत्री महोदय क्यों आते हैं ? सरकार की ज्वाइन्ट रिस्पोंसिबिलिटी होती है। इस बात को टाल कर वे नहीं जा सकते हैं ... (व्यवधान) यह आपकी जिम्मेदारी है, आप को जवाब देना है।

SHRI G. S. DHILLON: You have not heard first part of my reply. I said I will deal with the matters which are concerned with the Calling Attention matter. The other points which relate to the price of processed food or processed items, all that I can do is I will note them down and convey them to the concerned Department for their consideration.. (*Interruptions*)

Sir, I have already mentioned the points that have been considered by the Commission while determining the price of seeds, fertilizers, diesel, etc. So we have to take into account the cost of production, changes in output and input prices, trends in market prices, demand and supply, inter-crop price parity, effect on individual cost of structure, effect on general price level, effect on cost of living, the international market price situation, the parity between prices paid and prices received. So while we take those factors into consideration, we do have some guidelines which will help us in proper fixing of these prices.

So far as fertilizers are concerned, a concern was expressed about the sudden hike in the price. Though the prices of fertilizers were raised in January, 1986, yet these have been retained at 1981 levels. In between these five years, we had reduced the price by 10 per cent. But this had to be reversed. So far as the figures quoted by my friend, Mr. Virendra Verma and some others are concerned, I can say that to keep the fertilizer price within the limits of the farmer's capacity, the Government, while depending on our own plants and factories, have to import about 39 to 40 per cent from outside. We have a shortage. I have seen the figures. Import is done by China. It is done by many other countries. Some of the items which are components of the fertilizers in some cases are not available. So willingly or unwillingly we have to import them to manufacture it in the final form. I may say that about Rs. 2,000 crores is being paid as subsidy to keep the price low. As a Kiss to a sleeping man, the farmer does not know how the input price is kept low. Another point which has been made is that the cost of production of fertilizers is on the higher side in this country. But I have got the figures, in terms of kilograms of paddy required to buy one kilogram of nitrogen. The question was raised about nitrogen. In Bangladesh it is 1.79 Kg...

SHRI KALPNATH RAI: In Japan?

SHRI G. S. DHILLON: Please. In India, it is 3.57; in Indonesia, it is 1.18; in Malaysia, it is 4; in Pakistan it is 2.56; in the Philippines it is 4.17; in Sri Lanka

it is 1.82; and in Thailand, it is 4.35. The prices of fertilizers, if we consider them in this perspective, are quite comparable with those in other parts of the world.

While assessing the determinant factors, one basic point is kept in view, that is, there should be a margin of profit. But that profit should not be at the cost of the consumers, the labourers and some other weaker sections of the society, who ultimately are affected by the economy in general. But one thing about which I am very confident is that when three of the non-official Members join the Commission, the farmer's interest will be still better protected and lacuna of farmers' absence and lack of advice will be rectified. Sometimes, in a limited Commission, some points may not come. But when the Commissions consists of Members with experience in various fields, I very much hope that will add to the efficiency of the general working of the Commission and I honestly pray for that. Before becoming the Minister I have myself been advocating and I am very much there now and I think it should be my honest duty to see that this lacuna continues no more.

Then, Sir, some honourable Members made some very interesting and very useful points. Some honourable Members mentioned about irrigation, some mentioned about tractors and some about tyres.

SHRI KALPNATH RAI: Insecticides.

SHRI G. S DHILLON: It is already there. But I have seen the determining factors and the criteria that should be there. These are all there. If the Members so desire, I can send them the detailed list. It is quite big. Now, there is going to be a computerised side of it also. Instead of spending two years in calculating, and processing statistics cost data, we will spend less time and this will reduce the period of generating final cost estimates to a little less than half and that would be very helpful to us. If the prices are to be determined on the basis of latest cost estimates, these data should be with us within a minimum period of time so that we are able to pass them on to the Commission to arrive at a reasonable solution.

I have some opinions of some professors before me. Sir, the share of agriculture in the general economy of the country is 30.7 per cent. Here, as in the case of Japan and the USA, there is a general tendency that with the development of agriculture and development of our technology, the share, when it goes down, is not indicative of the fact that production has also gone down. But the experience is that when the share goes down, production rises, as in the case of Japan, and as in the case of the USA. The same is the case here. As its share in the general economy of the country goes down, our production and productivity have gone up. Now, an honourable Member—I think it was Mr. Mahajan—was asking why there should be a Commission for Agricultural Costs and Prices and why it should not be like the Bureau of Industrial Costs and Prices. I have tried to determine within a very short time, to find out the difference between the constitution of these two. When we say that there should be non-official Members from the farming community on the Commission for Agricultural Costs and Prices, in that Bureau, there is no non-official Member at all and the model and the structure of that Bureau do not help us when we compare it with the Commission for Agricultural Costs and Prices. This was the information which I thought I should convey to the honourable Member. It is because during the period for which the figures have been quoted, the cake was quite small and the agricultural sector seemed to be bigger. Now, with the expansion and development of the economy, the cake is quite big, the share of agriculture has naturally reduced in size. It does not mean that there is a progress on the negative side. Instead we find that there is more productivity and more production.

There was a very good suggestion from an hon. Member that it should be related to the wholesale price and the end price when it goes to the consumer,

[Shri G. S. Dhillon]

thereby avoiding this difference. I am myself interested in it. I would like a study of how much is the difference when it comes from the farmer, goes to the wholesale dealer and also when it passes from the wholesale dealer to the consumer through various intermediaries. In the course of time, I think we will have some study and if I find that it is inexcusable, I will certainly bring it to the notice of the House because in that case it will become a question deeply concerned with the welfare and interest of the farmer as to what he gets. When the farmer sells at a certain price and the consumer gets it at a much higher price and the rise is steep, whatever may be the reasons, we must know as to how to satisfy the farmer irrespective of the fact whether the end consumption in justified or not.

There was a point raised...

आपने मुझे पूछा पोटेटोज का क्या झगडा है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ऐसा किया । मैंने सारी, जिन्दगी में ऐसा नहीं सुना जैसे आज राज्य सभा में मैंने सुन लिया है कि पोटेटोज की कीमत बढ गई है कहीं आपका तो इसमें हिस्सा नहीं है । देखिये जरा जिम्मेदारी से बोला करिये । (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : मैं सरकार पर चार्ज करता हूं (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री पवन कुमार बांसल) राम अवधेश जी आपको बोलना है तो अपनी सीट से बोलिये ।

श्री जी० एस० ढिल्लों : मैं तो इस राज्य सभा में आया उस हाउस में मैम्बर. . . (व्यवधान) मैंने सोचा कि यहां मैम्बर अच्छा सवाल करेंगे . . . (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : यह सरकार पर मेरा चार्ज है कि आलू काभाव इतना क्यों बढ़ा है । इसलिये मैं आप पर चार्ज करता हूं और आप इसके लिये जिम्मेदार हैं । आप को जवाब यह देना चाहिये कि क्या आलू के भाव को आप कन्ट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं (व्यवधान) यह आप केटेगोरीकल जवाब दीजिये । (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री पवन कुमार बांसल) : आपने अपना प्वाइन्ट कह दिया है (व्यवधान) आप बैठ जाइये (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : हम लोग पत्थर के स्टेचू नहीं हैं कि सरकार जो बोलती रहेगी हम लोग सुनेंगे (व्यवधान) आप केटेगोरीकली जवाब दीजिये ।

श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि राज्य सभा में आने के बाद हम यह त्वस्को रखते हैं कि अच्छे सवाल किये जायेंगे (व्यवधान) मगर यहां अच्छे सवालात नहीं किये जा रहे हैं । यह तो मैम्बरों के खिलाफ जवाब चार्ज है (व्यवधान) यहां के मैम्बरान जो सवाल करते हैं सोच समझ कर करते हैं । आप को उनका जवाब देना चाहिये दे सकते हैं तो दीजिये (व्यवधान) ।

श्री जी० एस० ढिल्लों : यह किसी सवाल के जवाब में नहीं था । यह आलू के भाव वाले सवाल में अगर वह गलत है तो मैं माफी मांगता हूं ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : आप बोल दीजिये गलत है । यह मत कहिये कि राज्य सभा में (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : आप मेरे प्वाइंट का जवाब दीजिये (व्यवधान) सरकार रोकेगी या नहीं । दम से बोलिए, दम हो तो बोलिये नहीं तो विधवा विलाप करिये (व्यवधान)

5.00 P. M.

श्री जी० एस० ढिल्लों : आप ऐसा.. (व्यवधान) रवैया अख्तियार करने से रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री पवन कुमार बांसल): अब आप बैठिये ।

You cannot rise again and again.

श्री राम अवधेश सिंह : ये जवाब नहीं दे रहे हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री पवन कुमार बांसल) : मैं आपको बार बार वहां बात करने के लिये खड़ा नहीं होने दूंगा ।

Now, let the Minister continue.

श्री जी० एस० ढिल्लों : जो आपने सवाल रखे उन सारी चीजों पर विचार करना जरूर मेरी कोशिश है और उसका पता लगाना मेरा फर्ज बनता है (**व्यवधान**) मैंने तो बस यही कहा कि मैं आप से सवाल करने का तरीका जरा ज्यादा नर्म समझा था आप ऐसे जोश में आकर हमसे सवाल करते हैं । अगर आपको बुरा लगे तो मेरे बस की बात नहीं है ... (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : थोड़ा उम्र का सवाल है ।

श्री जी० एस० ढिल्लों : क्या करें ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : आप भी अपनी उम्र के अनुसार बोल रहे हैं ।

श्री जी. एस. ढिल्लों : दिल तो मेरा भी करता है कि मैं नौजवान ही रहूं लेकिन उम्र का तकाजा होता है ।

श्री राम अवधेश सिंह : उजले बाल तो काले कर लिये हैं ।

श्री जी. एस. ढिल्लों : जो प्रश्न आपने किये, आपने जो कहा उसका मैंने जवाब दे दिया ।

श्री राम अवधेश सिंह : नहीं दिया ... (**व्यवधान**)

श्री गुलाम रसुल मट्टू : अभी आपने फरमाया कि डिमांड एण्ड सप्लाई का मसला है । डिमांड एण्ड सप्लाई के मामले में यह आता है अगर आपकी डिमांड 2.20 रुपये में है तो सप्लाई 1 रुपये 1.62 पैसे में क्यों है ... (**व्यवधान**) जवाब आपका यह है कि आपकी मिनिस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखता है । यह समझ लीजिये कि हमारा मसला क्या है ।

†[جناب غلام رسول مٹو : آپنے فرمایا کہ ڈمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہے - ڈمانڈ اینڈ سپلائی کے معاملے میں یہ آتا ہے اگر آپکی ڈمانڈ 2.20 روپئے میں ہے - تو سپلائی ایک روپیہ باسٹھ پیسہ میں کیوں ہے - ... (مداخلت) ... اب آپکا یہ ہے - کہ آپکی منسٹری سے تعلق نہیں رکھتا ہے - سمجھ لیجئے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے -]

श्री जी० एस० ढिल्लों : मैंने अर्ज किया मैंने कहा था, जो गाइड लाइन होगी कमीशन के लिये उसमें डिमांड एण्ड सप्लाई .. (**व्यवधान**) मेरी तो अपनी राय नहीं है, जो गाइड लाइन उनको दी गयी है उन्हीं में है ।

श्री राम अवधेश सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं इसलिये मैं वाक आऊट कर रहा हूं ।

At this stage the hon. Member left the Chamber

श्री जी० एस० ढिल्लों : यह मैंने फीगर्स रखी हैं । सवाल उठाया गया था कि जो चीजें किसान को दी जाती हैं उनमें और जो किसान खरीदते हैं उनमें डिसपैरिटी नहीं होनी चाहिये, तो टर्म्स आफ ट्रेड में फर्क नहीं होना चाहिये । मेरे पास आफिसियल तौर पर 79–80 के बाद

†[ ]Translitration in Arabic script.

श्री जी० एस० ढिल्लों

100 इंडेक्स, फिगर रखकर जो आई है उसमें 1979-80 की अगर मान लो 100 आता है, प्राइसेज पेड 100 और टर्म्स आफ ट्रेड 100 तो 80-81 में 115, प्राइज पेड 117, टर्म्स आफ ट्रेड 98.5 उसमें कमी आई है। 81-82 में 120.1, प्राइसेज पेड 129.2 टर्म्स आफ ट्रेड वाले में 93 हो गया, इसी तरह से हम 84-85 पर आते हैं। प्राइसेज रिसीव्ड 154.5 प्राइसेज पेड 154.9 और 99.7 टर्म्स आफ ट्रेड में आ जाते हैं तो आलमोस्ट जो वह लेता है प्राइस और जिससे वह खरीदता है स्टेट पटिकल में तकरीबन बराबर है फेवर का फर्क आ जायेगा। यह मैंने सोचा आपकी नोटिस में ला दूं। जब आप अंग्रेजी बोले तो मैं अंग्रेजी में बोल रहा था, फिर आप हिन्दी में शुरू हो गये तो मैंने हिन्दी में बोलना शुरू कर दिया। बहुत से पाइन्ट कवर कर दिये हैं और कोई रह गया हो तो पूछ लीजिये।

श्री प्रमोद महाजन: मैंने पूछा था जो प्रोक्योरमेंट प्राइस आपने बताई है और जिसको आप रिम्यूनरेटिव प्राइस मानते हैं तो क्या कारेस्पोंडिंग आप बता सकेंगे जैसे अभी आपने तीन चीजों के प्रोक्योरमेंट प्राइज बतायें ...। Are they the same or the remunerative prices are a little bit more?

SHRI G.S. DHILLON: When I spoke earlier, I think perhaps you were not here. I said that the support prices are so fixed that the remunerative price is recommended in the real sense. In case the actual market price is higher than the support price, we do not come in the way. But in case prices fall, the Government extends market support at declared prices so that the farmer or the producer does not suffer the loss.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: I asked what according to your opinion are remunerative prices for these products.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): He has replied in his own way. Now we will take up special mentions.

श्री कल्पनाथ राय: अभी जवाब नहीं दिया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री पवन कुमार बांसल) जवाब हो गया है।

SHRI G. S. DHILLON: I have tried to answer all the points. Still, let me know if I have not been able to reply some points. I tried to cover almost all the points raised in this four and a half an hour debate I thought that I should reply some of the points collectively and some of them individually. But if still some point is left out, please let me know.

[**The Vice-Chairman (Shri H. Hanumanthappa)** in the Chair.]

REFERENCE TO THE EROSION OF LAND CAUSED BY THE BRAHMAPUTRA RIVER IN SEVERAL PARTS OF ASSAM

SHRIMATI BIJOLA CHAKRAVARTY (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to draw the attention to the havoc caused by the river Brahmaputra. The river Brahmaputra is a source of woes and misery to the people of Assam. It is not a new thing. It has been happening for the last 36 years since the devastating earthquake of August 15, 1950. The erosion of Brahmaputra valley is continuing unabated since then. The river Brahmaputra runs 720 kilometres in Assam. From Dibrugarh to Dumri this devastation caused by the river Brahmaputra is seen. Sir, the Dibrugarh town itself is threatened since 50s and it has not yet been protected. And then, Sir, there are adjoining tea gardens and they are being eroded solwly and gradually. There is the Auckland tea garden close by and this tea garden produces the export variety of tea and already half of this tea garden is eroded by the Brahmaputra river. There is no check. Secondly comes the Jorhat town, the prime town of Upper Assam and it too